



VAJIRAO & REDDY INSTITUTE

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918988885050



+918988886060

www.vajiraoinstitute.com



info@vajiraoinstitute.com

YOJANA MAGAZINE ANALYSIS

(योजना पत्रिका विश्लेषण)

(वर्ष का लेखा-जोखा)

(December 2023)

(Part III)

TOPICS TO BE COVERED

- भारत का उद्योग क्षेत्र
- कृषि और ग्रामीण विकास: प्रमुख पहल और उपलब्धियां

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



भारत का उद्योग क्षेत्र:

पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान:

- लॉजिस्टिक्स की कार्यकुशलता बढ़ाने और खर्च घटाने तथा देश में अंतरविभागीय विभाजनों को तोड़ने के लिए इस बात की आवश्यकता महसूस की गई है कि विभिन्न एजेंसियों के योजना निर्माण और अवसंरचना विकास के प्रयासों को एकीकृत किया जाए।

- वर्ष 2021 में शुरू की गई पीएम गतिशक्ति इसी दिशा में एक कदम है। इसमें समग्र शासन के दृष्टिकोण को अपनाया गया है। एकीकरण, तालमेल, प्राथमिकता निर्धारण



और अधिकतम परिणाम को हासिल करने के लिए इसके दो पहलू हैं।

- इनमें से पहला भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) आधारित प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय मास्टर प्लान का विकास है। इसके तहत सड़कों से लेकर रेलवे, विमानन, कृषि, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तक को जोड़ा जा रहा है।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- दूसरा पहलू त्रिस्तरीय संस्थागत व्यवस्था की स्थापना के जरिए बहुविध अवसंरचना और आर्थिक क्षेत्र के तालमेल के साथ विकास के लिए विभिन्न संबंधित मंत्रालयों और विभागों के प्रयासों को एकजुट करने के उद्देश्य से प्रशासनिक व्यवस्था करना है।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति:

- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 में शुरू की गई थी। यह लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए एक व्यापक अंतःविषय, क्रॉस-सेक्टरल बहु-क्षेत्राधिकार और व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार करती है। यह नीति पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की पूरक है।
- इसका उद्देश्य त्वरित और समावेशी विकास के लिए तकनीकी रूप से सक्षम संपूर्ण, कम लागत वाला लचीला, टिकाऊ और विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति:

- उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर नीति तैयार करने वाला मुख्य विभाग है। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रेषित धन के आधार पर भारत में आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश डेटा का रखरखाव और प्रबंधन भी करता है।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने की दृष्टि से **एक उदार नीति लागू की गई है जिसमें स्वचालित मार्ग के तहत अधिकांश क्षेत्रों/गतिविधियों में 100 प्रतिशत तक FDI की अनुमति दी गई है।**
- जून 2017 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को समाप्त करने के बाद, FDI की मंजूरी देने की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है, जिसमें मौजूदा FDI नीति और फेमा के तहत FDI के लिए आवेदनों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और उस पर सरकार की मंजूरी से संबंधित कार्य अब संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जाता है।

मेक इन इंडिया:

- 'मेक इन इंडिया' पहल 2014 में निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम श्रेणी के बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और **भारत को विनिर्माण डिजाइन और नवाचार का केंद्र बनाने के लिए शुरू की गई थी।**
- यह अनूठी पहल 'वोकल फॉर लोकल' जैसी पहलों में से एक है जिसने भारत के विनिर्माण क्षेत्र को दुनिया भर में बढ़ावा दिया।
- इस पहल ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है **और वर्तमान में मेक इन इंडिया 2.0 के तहत 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।**

ADDRESS:



उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना:

- भारत को 'आत्मनिर्भर' बनाने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए PLI (उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन) योजनाओं की घोषणा की गई।
- PLI योजनाओं का **प्रमुख उद्देश्य मुख्य योग्यता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना और भारतीय कंपनियों और निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना** है ताकि वे वैश्विक बाजारों में प्रवेश कर सकें और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के अनुकूल बन सकें।
- इससे, अगले 5 वर्षों में उत्पादन, रोजगार और आर्थिक विकास में वृद्धि की उम्मीद है।

स्टार्टअप इंडिया:

- 'स्टार्टअप इंडिया' पहल 2016 में शुरू की गई थी। इस पहल का उद्देश्य नए स्टार्टअप के विकास के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देना है।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



VAJIRAO & REDDY INSTITUTE

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918988885050
+918988886060



www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com



- यह **पहल उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए तीन प्रमुख स्तंभों यानी (क)** सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग, **(ख) वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन, और (ग) उद्योग-अकादमिक साझेदारी और बिजनेस इन्क्यूबेशन में मदद उपलब्ध कराती है।**
- उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा **15 मई 2023 तक 674 जिलों में 57 क्षेत्रों में कुल 99,371 स्टार्टअप को मान्यता दी गई है।**
- **फंड ऑफ फंड्स (FFS):**
 - उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने स्टार्टअप्स की फंडिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए **10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ फंड ऑफ फंड्स (FFS) की स्थापना की।**
 - इस योजना का उद्देश्य नवाचार संचालित उद्यमिता में तेजी लाना और स्टार्टअप के लिए बड़े स्तर पर इक्विटी जुटाना जैसे संसाधन शामिल है।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



कृषि और ग्रामीण विकास: प्रमुख पहल और उपलब्धियां

परिचय:

- आत्मनिर्भर भारत की राह में ग्रामीण लोगों की आजीविका सुरक्षा और वित्तीय सशक्तिकरण भारत सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएं हैं।
- सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए, इस वर्ष गांवों में समावेशी विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में बदलाव में तेजी लाने के लिए कई कार्यनीतिक कदम उठाए हैं।
- केंद्र प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को लाभप्रदता, उत्पादकता और समृद्धि के केंद्र के रूप में विकसित करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, चल रही योजनाओं और नई पहलों के लिए 2023-24 के लिए बजट आवंटन में काफी वृद्धि की गई है।
- प्रधानमंत्री ने 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस (3 जुलाई 2023) को संबोधित करते हुए कहा, **“सरकार कृषि और किसानों पर औसतन सालाना 6.5 लाख करोड़ रुपये**



ADDRESS:



से अधिक खर्च कर रही हैं। दूसरी ओर ग्रामीण विकास मंत्रालय को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1,59,964 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

कृषि क्षेत्र में उच्च मानकों की स्थापना:

● मोटा अनाज पर बल:

- भारत सरकार के प्रस्ताव के आधार पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को 'अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष' घोषित किया था। मोटा अनाज के उत्पादन, प्रसंस्करण तथा विपणन को बढ़ावा देने और भारत को उसके वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक मिशन शुरू किया गया था।
- कई प्रचारात्मक और सहायक योजनाओं के कारण मोटा अनाज की उपलब्धता बढ़कर प्रति व्यक्ति प्रति माह 14 किलोग्राम हो गई है।
- मोटा अनाज मिशन ने मोटा अनाज की खेती में लगे लगभग 2.5 करोड़ किसानों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

- **रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन:** खाद्यान्न उत्पादन के मोर्चे पर देश ने 2022-23 में क्रमशः 330 मिलियन टन और 352 मिलियन टन के अनुमानित उत्पादन के साथ

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



खाद्यान्न और बागवानी उपज दोनों के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया। वर्ष 2022-23 में प्रमुख खाद्यान्न- धान (चावल), और गेहूं ने क्रमशः 135 मिलियन टन और 110 मिलियन टन का सर्वकालिक उच्च उत्पादन दर्ज किया।

- **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP):** उत्पादन की अखिल भारतीय औसत लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करने की सरकार की नीति के अनुरूप सरकार ने विपणन योजना 2024-25 के लिए अनिवार्य रवि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की है। न्यूनतम समर्थन मूल्य-एमएसपी में वृद्धि का पैटर्न खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, किसानों की आय बढ़ाने और विश्व पर निर्भरता तथा आयात को कम करने के लिए तिलहन और दलहन के लिए फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के सरकार के इरादे को दर्शाता है।
- **अनाज भंडारण योजना:** सरकार ने इस वर्ष 'सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना' की सुविधा की घोषणा की है। इस योजना में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएल) के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कृषि-बुनियादी ढांचे, जैसे गोदाम कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयां आदि की स्थापना

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



शामिल है। एक लाख से अधिक प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और 13 करोड़ से अधिक सदस्य किसानों के दूरगामी नेटवर्क के साथ इस योजना में भोजन की बर्बादी में पर्याप्त कमी खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और किसानों की आय को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है।

कृषि विकास के लिए पहल:

- **पीएम-प्रणाम योजना:** बजट प्रस्ताव (2023-24) के अनुसार, सरकार ने 'पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नॉरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर-अर्थ' (पीएम-प्रणाम) योजना को मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य धरती मां के स्वास्थ्य को बचाने के लिए उर्वरकों के टिकाऊ और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देकर, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाकर, वैकल्पिक खेती को बढ़ावा देकर और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को लागू करके राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन का समर्थन करना है।
- **कृषि में विशिष्ट आईटी-आधारित पहल:**
 - इनमें से पहली- **किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)** है जिसे किसान ऋण पोर्टल कहा जाता है। सरकार ने 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2023 तक 'घर घर केसीसी

ADDRESS:



अभियान' नामक एक विशेष अभियान शुरू किया। इसका लक्ष्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लगभग 1.5 करोड़ लाभार्थियों को जोड़ना है जो अभी तक केसीसी योजना से नहीं जुड़े हैं।

- दूसरी-एक **व्यापक विड्स (मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम) मैनुअल लॉन्च किया गया** था। विड्स तालुक/ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर स्वचालित मौसम स्टेशनों और वर्षा मापकों का एक नेटवर्क स्थापित करने का एक प्रयास है। मौसम डेटा से फसल प्रबंधन, संसाधन आवंटन सुधार करने और जोखिम कम करने में मदद मिलेगी।

ग्रामीण भारत के लिए समृद्धि का मार्ग:

- सुरक्षा जाल बनाने और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के विशिष्ट एजेंडे के साथ, राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के केंद्र में ग्रामीण निवासी हैं जो आबादी का लगभग 65 प्रतिशत हैं।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय देश में ग्रामीण विकास के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए 2024-30 के लिए एक मध्यम अवधि की योजना और 2024-47 के लिए एक दीर्घकालिक योजना बनाने के लिए तैयार है।

ADDRESS:



- **दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन:**

- इस अभियान का लक्ष्य दो करोड़ 'लखपति दीदियों एसएचजी दीदियों' को सक्षम बनाना है, जो प्रति परिवार प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपये की स्थायी आय अर्जित कर सकें।
- 'संगठन से समृद्धि' किसी भी ग्रामीण महिला को पीछे न छोड़ना' इस मिशन के तहत एक और राष्ट्रीय अभियान था, जिसका उद्देश्य कमजोर और हाशिए पर रहने वाले ग्रामीण परिवारों से अतिरिक्त एक करोड़ महिलाओं को एसएचजी में शामिल करना था।
- अभियान के सफल समापन पर कुल 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएँ स्वयं सहायता समूह आंदोलन का हिस्सा होंगी।

- **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान:** सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय शासन और आर्थिक विकास के जीवंत केंद्रों के रूप में फिर से कल्पना करने पर ध्यान देने के साथ अपने 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' (1.04.2023 से 31.3.2026) को नया रूप दिया है। इसके नौ विषयों में गरीबी मुक्त, स्वस्थ, बाल-हितैषी, जल-पर्याप्तता, स्वच्छ और हरित आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सामाजिक रूप से सुरक्षित सुशासित और महिला-अनुकूल गांव शामिल हैं।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- **जल जीवन मिशन:** कल्याणकारी योजनाओं में जल जीवन मिशन ने 13 करोड़ घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने के कनेक्शन प्रदान करने का मील का पत्थर हासिल कर लिया है। जीवन बदलने वाले इस मिशन ने एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए, ग्रामीण नल कनेक्शन कवरेज को शुरुआत (अगस्त 2019) के केवल 3.23 करोड़ घरों में बढ़ाकर केवल चार वर्षों में 13 करोड़ कर दिया है।
- **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का विस्तार:** इस वर्ष सरकार ने तीन वर्षों (2023-24 से 2025-26) में 75 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इससे कुल लाभार्थियों को संख्या 10.35 करोड़ हो जाएगी। उज्ज्वला के दूसरे चरण के मौजूदा तौर-तरीकों के अनुसार लाभार्थियों को पहला रिफिल और स्टोव भी मुफ्त प्रदान किया जाता है।
- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना:** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने अपने सभी कार्यक्षेत्रों/कार्यक्रमों के तहत 7,45,780 किमी लंबी बनाने में मदद की है। सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि इस योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार सृजन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



VAJIRAO & REDDY INSTITUTE

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918988885050
+918988886060



www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com



- **स्वच्छ भारत मिशन (SBM):** इस वर्ष स्वच्छ भारत मिशन के नौ वर्ष पूरे हो गए हैं और 75 प्रतिशत से अधिक गांवों को ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) से मुक्ति इस संबंध में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण चरण- दो देश भर में लाखों लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाने में सहायक रहा है।
- सरकार ने अधिक न्यायसंगत और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर अपना जोर जारी रखा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण, सक्रिय सामाजिक-आर्थिक समावेशन तथा एकीकरण के माध्यम से जीवन और आजीविका में बदलाव लाना है।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)